

SHRI MOINUL HAQUE CHOU-DHURY : So far as the Industrial Reconstruction Corporation is concerned, I am afraid, I have not got the figures. The Textile Corporation has so far taken over 45 textile mills.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : May I know whether the government propose to take some of these ailing industries in the identified backward areas where though the industries have been started, they have not been doing well. If so may I know whether any special consideration is shown to such of those industries in the identified backward areas ?

SHRI MOINUL HAQUE CHOU-DHURY : Whenever we take up a closed mill we do not make any distinction between backward and other areas. But when we take the final decision certainly, one of the considerations is the backwardness of that area.

Radio Station Trichur

*664. **SHRI C. JANARDHANAN :** Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government propose to raise the present status of the Radio Station at Trichur to an independent Broadcasting Station; and

(b) if so, the time by which it is expected to be implemented ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI NANDINI SATPATHY) : (a) Yes, Sir.

(b) September, 1972.

SHRI C. JANARDHAN : Thank you. I have no supplementaries.

SHRI R. BALAKRISHNA PILLAI : May I know whether the government propose to raise the status of the Alleppy radio station, as the most powerful station in South India ?

MR. SPEAKER : He has gone from Trichur to Alleppy.

SHRI R. BALAKRISHNA PILLAI : Since all the Trichur programmes are relayed

by the Alleppy station, it is a related question.

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : In Alleppy we have a 100 kw medium wave transmitter. If the Trichur station is up-graded, naturally, the programme will be transmitted over wide areas and most parts of Kerala will be covered.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN : May I know from the Minister whether it is a fact that the Alleppy station of the AIR is defective ?

MR. SPEAKER : This question does not arise out of the main question, which was about Trichur station.

टेलीविजन सेटों के निर्माण में वृद्धि

*665. डा० सकुटा प्रसाद : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टेलीविजन सेटों के निर्माण में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बारे में सम्बन्धित कम्पनी को कोई आदेश दिये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो किस कम्पनी को और कितने उत्पादन के लिये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(क) जी हाँ, संस्वीकृत धारिता/क्षमता 40,000 टी० बी० सेट प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,28,000 सेट प्रतिवर्ष कर दी गई है।

(ख) तथा (ग). संगठित क्षेत्र में उन सरकारी तथा निजी क्षेत्र के युनिटों के नाम जिन्हें सेटों की संख्या के साथ टी० बी० सेट बनाने के लिये औद्योगिक लाइसेंस/आवश्यक जारी किये गये हैं नीचे सारणी में अंकित हैं। इन युनिटों को 1,10,000 सेटों को धारिता नियत करने के अतिरिक्त 1,18,000 सेटों को धारिता के लिये लघु-मध्यम क्षेत्र में 45 युनिटों को प्राधिकृत किया गया है।

क्रम संख्या	संगठित क्षेत्र में निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र युनिटों के नाम	टी० वी० सैटों के लिये धारिता जिन्हें पूर्णतः लाइसेंस दिए गए	टी० वी० सैटों के नई धारिता जिन्हें प्राथम्य पत्र जारी किये गये
1.	जे० के० इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर	10,000	10,000
2.	टेलोरेड, बम्बई	10,000	10,000
3.	जोन प्रसाद, श्री नगर	10,000	—
4.	इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इडिया, हैदराबाद	20,000	—
5.	तामिलनाडु स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन तथा श्री ओवेल रेड्डी, मद्रास	—	10,000
6.	रेमको बेंगलूर	—	5,000
7.	केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन	—	5,000
8.	राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन	—	5,000
9.	पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन	—	5,000
10.	हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन	—	5,000
11.	उडिसा स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन	—	5,000
		50,000	60,000
	योग	1, 10,000	

डा० संकटा प्रसाद : टी. वी. सैटों के बढ़ते हुए उत्पादन के साथ क्या उनकी कीमतों में कमी होने की गुंजाइश है ?

श्री कुच्छल चन्द्र बंत : कीमतों में कर्षा करने की कोशिश होगी और इस तरह की कोशिश होगी की बड़े स्केल में इस के कम्पोनेन्ट्स बनाये जाय तथा बड़े स्केल पर टी० वी० सैट्स बनाये जाये ताकि इन के दाम गिर सकें। छोटे स्क्रीन के साथ ट्रांजिस्ट्राइज्ड टी० वी० सैट्स बनाने का भी विचार है, ताकि दाम कम हो सकें।

डा० संकटा प्रसाद : क्या यह सही है कि प्रोड्युट सेंटर पब्लिक सैक्टर को विशेषा मुकामान पहुंचाने की कोशिश करता है ? अगर ऐसा है

तो सरकार इस के बारे में कौन से कदम उठ रही है ?

सभ्यता महोदय : प्रथी उन को बन तो लेने दीजिये।

श्री कुच्छल चन्द्र बंत : इस में तो यह सवाल उठता नहीं है क्योंकि जो नये लाइसेंस दिये गये हैं, वे या तो पब्लिक सैक्टर में हैं, एक तामिलनाडु में है, जिस में तामिलनाडु इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन की संबोर्टरी होगी, बाकी स्टास स्कैस सैक्टर में है। जैसा स्टेटमेंट में बिया गया है 60 परसेन्ट से ज्यादा स्टास स्कैस सैक्टर में है। लम्बे 18 हजार सैट्स के लिये स्टास स्कैस के 45 यूनिट्स को संस्थान दी-गई है, इस

लिये स्माल स्केल सैक्टर में इसका उत्पादन बढ़ाया जायेगा। लेकिन जो दो बड़े यूनिट्स पहले से प्राइवेट सैक्टर में कायम हैं, उनको एक्सपेंशन की इजाजत दी गई है इनके अलावा प्राइवेट सैक्टर में बड़े स्केल पर और कोई इजाजत नहीं दी गई है।

SHRI R. S. PANDEY : Is it not a fact that Hindustan Aeronautics has applied for a licence for a new television set, which is pending so long and no action has been taken on it for the last two years? In the meanwhile some licences were given to the private sector. Why this preference to the private sector at the cost of the public sector?

SHRI K. C. PANT : I am sorry my previous answer has made no impact on the hon. Member. Coming to the question of Hindustan Aeronautics, this application was rejected by the Electronics Commission.

MR. SPEAKER : I think this question was answered in the House earlier.

SHRI K. C. PANT : There are reasons for it which I can give.

SHRI R. S. PANDEY : Sir, I seek your protection. The statement of the Defence (Production) Minister the other day gave the impression that the application is pending and that is why I put the question.

SHRI S. M. BANERJEE : He can raise it in the party meeting.

MR. SPEAKER : There is no question of protection. It is all about production.

श्री बिभूति मिश्र : पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर दोनों को बिल्ट कर किसने टेली-विजन सेट्स पैदा होते हैं और हिन्दुस्तान में किसने सेटों की जरूरत है? जब प्रचार मंत्री श्री इस मंत्रालय में थीं, तब उन्होंने कहा था कि इसको हिन्दुस्तान में जल्दी से जल्दी बढ़ाया दिया जायगा ताकि सब लोगों को टेलिविजन का फायदा हो सके, लेकिन इस समय तो इस का फायदा केवल दिल्ली को मिलता है और अबहू नहीं मिलता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जहां तक मांग की प्रश्न है—ऐसा अनुमान लगाया गया है कि बीबी पंचवर्षीय योजना के अंत तक दो लाख टेलिविजन सेटों की आवश्यकता हर साल पड़ेगी, इसीलिये इस समय 2 लाख 28 हजार टेलिविजन सेट्स सालाना बनाने की कैपेसिटी संकलन की गई है।

दूसरी बात यह है कि जो संकलन हुए हैं, स्माल स्केल और बड़े स्केल में सब मिलाकर वह सारे देश में फैले हुए हैं। दिल्ली नहीं बल्कि सारे देश में फैले हुए हैं। बल्कि जो वक्तव्य मैंने दिया है उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे तो स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन्स हैं मसलन तमिल-नाडु स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, बंगलौर का पब्लिक सैक्टर प्रोजेक्ट है, केरल स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, उड़ीसा स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, हैदराबाद में एलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, श्रीनगर में एक प्रोजेक्ट है और बम्बई तथा कानपुर में भी है। मैं सारी फेहरिस्त दे सकता हूँ लेकिन इससे अन्दाज़ा हो गया होगा कि यह सारे देश में फैले हुए हैं।

श्री राम सूरत प्रसाद : मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय के जानाना चाहता हूँ कि ट्रांजिस्टर-टैराइज्ड टेलिविजन सेटों का अधिक से अधिक भाषा में कब तक उत्पादन होगा ताकि छोटे से छोटा शरीरने वाला भी उससे लाभान्वित हो सके?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मंत्री तो ट्रांजिस्टर-इज्ड सेट्स का उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। बड़े स्केल पर मंत्री तो जो साधारण सेट हैं बड़ी बन रहे हैं लेकिन उम्मीद है कि इस साल के आखीर तक ट्रांजिस्टर-इज्ड टी.वी. सेट्स बनने लगेंगे।